सदाराम सूर्यनारायण और अन्य

बनाम

कल्ला सूर्य कंथम और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2758/2004)

22 अक्टूबर 2010

[मार्कंडेय कैटजू और टी.एस. ठाकुर, जे.जे.।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 वसीयत का निष्पादन वसीयतकर्ता के पक्ष में पूर्ण रूप से संपत्ति की वसीयत करना उसकी बेटियाँ वसीयत का उत्तरार्द्ध भाग निहित करने के लिए अभिप्रेत है। उनकी मादा संतानों में समान संपत्ति की व्याख्या आयोजित: वसीयत से यह स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता ने एक बनाया था अपनी बेटियों के पक्ष में स्पष्ट और पूर्ण वसीयत उत्तरार्द्ध तक ऐसी सभी संपत्ति उपलब्ध रही। निधन के समय वसीयतकर्ताओं के हाथों में थे अपनी मादा संतानों को हस्तांतरित करेंबाद वाला भाग अनावश्यक है चूँकि यह वसीयतकर्ता के स्पष्ट इरादे के प्रतिकूल था। अपनी बेटियों के पक्ष में पूर्ण वसीयत करना दूसरे भाग में की गई शर्त का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा वसीयतदार संपत्ति के पूर्ण मालिक हैं उन्हें वसीयत कर दी गई उनके निधन पर संपत्ति का स्वामित्व हो गया।

उनके द्वारा उत्तराधिकार के सामान्य कानून द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा उनके उत्तराधिकारी और वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार नहीं।

मूल मालिक ने कुछ संपत्तियों की वसीयत अपनी बेटियों 'एसए' और 'एसआर' के पक्ष में कर दी। यह निर्धारित किया गया था कि 'एसए' और 'एसआर' की मृत्यु के बाद संपत्तियां अपनी मादा संतानों पर हावी होंगी। 'एसए' की बिना वसीयत के मृत्यु हो गई। अपीलकर्ताओं, 'एसए' के पुत्रों ने कब्जा कर लिया। जी की संपत्ति 'एसए' के पक्ष में वसीयत कर दी गई। उत्तरदाता की बेटी 'एसए' और अन्य ने घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया। वाद संपत्ति पर स्वामित्व और कब्जे की वसूली के लिए वसीयत में निहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए। परीक्षण अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया. उच्च न्यायालय ने ए को रद्द कर दिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया और मुकदमे पर फैसला सुनाया गया। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने तत्काल अपील दायर की।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 यह ध्यान से पढ़ने से स्पष्ट है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 84, 85, 86 और 87, 1925 कि एक वसीयत की व्याख्या करते समय, अदालतें उतनी ही दूर तक जाएंगी। यथासंभव ऐसी व्याख्या रखें जिससे कोई भी बच सके। एक वसीयतनामा का हिस्सा

निरर्थक हो रहा है। न्यायालय इरादे को प्रभावी करने के लिए वसीयत की व्याख्या भी करेगा जहां तक संभव हो वसीयतकर्ता का। प्रत्येक दस्तावेज़ की विशिष्ट व्याख्या की जानी चाहिए। जिन परिस्थितियों में इसे निष्पादित किया गया है और वसीयतकर्ता द्वारा प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए। यह वास्तव में डी की धारा 82 की आवश्यकता है। उत्तराधिकार अधिनियम भी उतना ही अर्थ प्रदान करता है वसीयत में किसी भी खंड का पूरा विवरण एकत्र किया जाना चाहिए। उपकरण और सभी भागों के साथ समझा जाना चाहिए। एक दूसरे का संदर्भ [पैरा 16। [821-एफ-एच; 822-ए]

1.2 यह खंड 6 को ध्यान से पढ़ने से स्पष्ट है वसीयत वही एक स्पष्ट और निरपेक्ष बनाती है वसीयतकर्ता की बेटियों के पक्ष में वसीयत का उपयोग जैसे शब्द "बिक्री, उपहार, बंधक आदि के पूर्ण अधिकार।" वसीयतकर्ता द्वारा नियोजित का इरादा बनाते हैं। वसीयतकर्ता प्रचुर मात्रा में स्पष्ट। इसके बाद वसीयतकर्ता ने ऐसा चाहा उनकी बेटियों की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति उनके पास चली गई। केवल उनकी महिला उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाएगा। कोई नहीं है विवाद है कि वसीयतकर्ता ने बिना किसी अनिश्चित शर्तों के बनाया था। अपनी बेटियों के पक्ष में एक पूर्ण वसीयत प्रस्तुतीकरण कि 'एसए' की पूर्ण संपत्ति जी के पास होनी चाहिए। इसे केवल एक जीवन संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए, हालांकि पहली नज़र में यह आकर्षक है। शरमाना, करीब से जांच में टिक नहीं पाता। ऐसा

कहा जाता है क्योंकि किसी की भी व्याख्या का अंतिम उद्देश्य दस्तावेज़ का उद्देश्य सत्य की खोज करना और उसे क्रियान्वित करना है। निष्पादक का इरादा, तत्काल मामले में, वसीयतनामा, वसीयतकर्ता का इरादा पूर्ण वसीयत करना है अपनी बेटियों के पक्ष में स्पष्ट है। दूसरी बात, अभिव्यक्ति "मेरी बेटियों के निधन के बाद बरकरार रखी गई।" और शेष संपत्ति उनकी महिलाओं को हस्तांतरित हो जाएगी। केवल बच्चों के लिए" सेंसू की राशि सख्त नहीं होती है के पक्ष में पहले की गई वसीयत के विपरीत वसीयत करना वसीयतकर्ता की बेटियाँ निकाली गई अभिव्यक्ति करती है वसीयत की पूर्ण प्रकृति से अलग न हों बेटियों का एहसान। [पैरा 6 और 17। [815-ए-बी; 822 सी-डी।

1.3 वह सब जो वसीयतकर्ता द्वारा प्राप्त करने का इरादा है खंड 6 का उत्तरार्द्ध उनका हस्तांतरण था। महिला संतानों के पास ऐसी सभी संपत्तियां थीं जो उपलब्ध रहीं उनके निधन के समय वसीयतकर्ताओं के हाथों में। जाहिर तौर पर ऐसा कोई हस्तांतरण नहीं होगा। उक्त के संदर्भ में महिला संतानों पर संपत्ति खंड यदि वसीयतकर्ताओं ने संपत्ति बेचने या उपहार में देने का निर्णय लिया है। उन्हें वसीयत कर दी गई क्योंकि वास्तव में उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार था। वसीयत की शर्तों के तहत. इस प्रकार, कोई वास्तविक नहीं है। पूर्ण वसीयत के बीच संघर्ष जो पहला भाग है वसीयत के खंड 6 का निर्माण और दूसरा भाग उक्त खंड जो क्या और यदि के हस्तांतरण से संबंधित है। वह सब कुछ जो वसीयतकर्ताओं के हाथ में

रहता है। खंड 6 के दो भाग विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, अर्थात्, वसीयतकर्ताओं पर पूर्ण स्वामित्व निहित करना बेचने, उपहार देने, गिरवी रखने आदि के अधिकार तथा अन्य विनियमन ऐसी चीज़ों का हस्तांतरण जो ऐसी बिक्री, उपहार या हस्तांतरण से बच सकती हैं। उनके द्वारा इस तथ्य के कारण उत्तरार्द्ध भाग निरर्थक है कि यह के स्पष्ट इरादे के प्रतिकूल था। उसके पक्ष में पूर्ण वसीयत करने में वसीयतकर्ता बेटियाँ यह अनावश्यक भी हो सकता है क्योंकि वसीयतकर्ताओं ने पूर्ण स्वामित्व के अपने अधिकारों का प्रयोग किया और इस प्रकार बिक्री से ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा सके। अगली पीढ़ी की महिलाएँ या अन्यथा शर्त खंड 6 के दूसरे भाग में बनाया गया एच बिल्कुल भी नहीं था। वसीयतकर्ताओं को इसके पूर्ण स्वामी होने से प्रभावित करें। संपत्ति उन्हें वसीयत कर दी गई। परिणाम यही होगा उनके निधन पर संपत्ति का स्वामित्व उनके पास रहेगा। उत्तराधिकार के सामान्य कानून द्वारा उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाता है और वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित वसीयत के संदर्भ में नहीं। [पैरा17। [823-ए-एफ।

1.4 उच्च द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और ट्रायल कोर्ट ने इसे पारित कर दिया है। [पैरा 18। [823-जी)

ससीमन चौधुरेन और अन्य। बनाम शिब नारायण चौधरी और अन्य. एआईआर 1922 पीसी 63; (कुंवर) रामेश्वर बख्श सिंह और अन्य। वि.

{ठकुराइन) बा/राज कुआर. और अन्य. एआईआर 1935 पीसी 187; राधा सुंदर दत्ता बनाम मोहम्मद. जहदुर रहीम और अन्य. 1959 एससीआर 1309; रामकिशोर लाल बनाम कमल नारायण (1963) सप्लीमेंट 2 एससीआर 417; मौलेश्वर मणि और अन्य। बनाम जगदीश प्रसाद और अन्य। (2002) 2 एससीसी 468; प्यारे लाल वी.रामेश्वर दास (1963) सप्लिमेंट 2 एससीआर 834; रामचन्द्र शेनॉय और अन्य. वी. श्रीमती हिल्डा ब्राइट और अन्य। 1964 (2) एस.सी.आर 722; काइवेलिका/अंबुन्ही (मृत) लार्स द्वारा। और अन्य. वी. एच. गणेश भंडारी (1995) 5 एससीसी 444 – संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

एआईआर 1922 पीसी 63	संदर्भित	पैरा 4
एआईआर 1935 पीसी 187	संदर्भित	पैरा 8
1959 एससीआर 1309	संदर्भित	पैरा 9
(1963) पूरक 2		
एससीआर 417	संदर्भित	पैरा 10
(2002) 2 एससीसी 468	संदर्भित	पैरा 11
(1963) अनुपूरक 2		
एससीआर 834	संदर्भित	पैरा 12

1964 (2) एससीआर

722 संदर्भित पैरा 13

(1995) 5 सेकंड 444 संदर्भित पैरा 14

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या. 2758/2004

उच्च न्यायालय हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के अपील संख्या 1530/1998 में निर्णय एवं आदेश दिनांकित 04.03.200 से।

अपीलकर्ताओं के लिए वाई राजा गोपाल राव।

आई. वेंकटनारायण, ए. चंद्रमोहन, टी. अनामिका उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

टी.एस. ठाकुर, जे.

1 विशेष अनुमति द्वारा यह अपील आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 4 मार्च, 2003 के एक आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके तहत 1998 की सिविल अपील संख्या 1530 को अनुमति दी गई है। यह निर्णय और आदेश द्वितीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है। 1991 के ओएस नंबर 32 में विशाखापत्तनम को खारिज कर दिया गया और वादी और प्रतिवादी द्वारा दायर कब्जे के मुकदमे को मुकदमे की तारीख से फैसले की तारीख तक प्रति माह 800 रुपये की दर

से लाभ देने का आदेश दिया गया। मुकदमा जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है।

2 अपीलकर्ता स्वर्गीय श्रीमती अप्पलानरसम्मा के पुत्र हैं। जबकि प्रतिवादी सदाराम अप्पलानरसम्मा बेटी और दामाद हैं। विवादग्रस्त संपत्ति में चार पूर्वी हिस्से दो भूतल पर और दो पहली मंजिल पर शामिल हैं [रेलवे न्यू कॉलोनी। विशाखापत्तनम में स्थित दरवाजा संख्या 44- 23- 35/7। 44- 23- 35/6। 44- 23- 35/1 और 44- 23- 35 मूल रूप से स्वर्गीय श्रीमती कल्ला जग्गयम्मा के स्वामित्व में था। जिनका 5 जुलाई। 1981 को निधन हो गया। वे अपने पीछे चार बेटों के अलावा दो बेटियों को छोड़ गईं जिनका नाम श्रीमती सदाराम अप्पलानरसम्मा और श्रीमती सदाराम रामनम्मा यह विवाद में नहीं है कि मृतक श्रीमती कल्ला जग्गयम्मा द्वारा दिनांक 4 सितंबर। 1976 को निष्पादित वसीयत के अनुसार। की वसीयत के पैरा 6 में आइटम 2 में उल्लिखित संपत्ति उनकी ऊपर उल्लिखित दो बेटियों के पक्ष में इस शर्त के साथ दी गई थी कि उनकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति उनकी महिला संतानों को हस्तांतरित हो जाएगी। श्रीमती सदाराम अप्पलानरसम्मा प्रथम वादी की मां और प्रतिवादी 1 से 6 सदाराम सूर्यनारायण। सदाराम ईश्वरराव। सदाराम देवानंद। सदाराम रमण। सदाराम सत्यनारायण और सदाराम रामू की 11 जनवरी। 1990 को बिना वसीयत मृत्यु हो गई। वादी का मामला यह है कि प्रतिवादी 1 से 6 यानी स्वर्गीय अप्पलानारसम्मा के बेटों ने श्रीमती कल्ला जग्गयम्मा द्वारा

निष्पादित वसीयत के आइटम नंबर 2 सहित संपत्ति पर कब्जा कर लिया। स्वर्गीय अप्पलानारसम्मा की बेटी के रूप में वादी नंबर 1 को हस्तांतरित कर दिया था और श्रीमती कल्ला जग्गयम्मा द्वारा निष्पादित वसीयत में निहित शर्तें। इसलिए वादी प्रतिवादियों ने ओएस नंबर 32/91 दायर किया। जिसमें उन्होंने अन्य राहतों के अलावा मुकदमे की संपत्ति पर स्वामित्व की घोषणा और उसके कब्जे की वसूली के लिए डिक्री की मांग की।

3. वर्तमान अपील में प्रतिवादी अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के अलावा यह दलील देते हुए मुकदमा लड़ा कि स्वर्गीय श्रीमती सदाराम अप्पलानारसम्मा ने अपने पक्ष में निष्पादित वसीयत के तहत संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व हासिल कर लिया था और 5 जनवरी। 1981 की वसीयत के अनुसार उन्होंने प्रतिवादी को संबंधित संपत्ति की वसीयत कर दी थी। जिसे वे उसके मालिक के रूप में अपने कब्जे में रखने के हकदार थे।

4. पक्षों की दलीलों पर ट्रायल कोर्ट ने चार मुद्दे फ्रेम किए। पक्षों को अपने संबंधित मामलों के समर्थन में सबूत पेश करने की अनुमति दी। लेकिन अंततः मुकदमे को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि वसीयत का निष्पादन श्रीमती कल्ला जग्गयम्मा द्वारा किया। साबित कर दिया गया था और उक्त वसीयत के अनुसार संपत्ति पूरी तरह से उत्तराधिकारी श्रीमती सदाराम अप्पलानारसम्मा को हस्तांतरित हो जाएगी। वादी का दावा इस शर्त के आधार पर संपत्ति सदाराम अप्पलानारसम्मा की

मृत्यु के बाद संपत्ति उसकी महिला संतानों को हस्तांतरित हो जाएगी। खारिज कर दिया गया। व्यथित होकर वादी ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में अपील की। जिसने हमारे समक्ष दिए गए निर्णय से ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को पलट दिया और मुकदमे को डिक्री कर दिया। ऐसा करते हुए उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निम्न निर्णयों का पालन कियाकैवेलिक्कल अंबुन्ही जरिये वारिस व अन्य बनाम एच गणेश भंडारी (1995) 5 एससीसी 444 रामचन्द्र शेनॉय व अन्य बनाम श्रीमती हिल्डा ब्राइट और अन्य 1964 (2) एससीआर 722 व प्रिवी काउंसिल का निर्णय ससीमन चौधरायन व अन्य बनाम शिवनारायण चौधरी व अन्य एआईआर 1922 पीसी 63 व प्यारेलाल बनाम रामेश्वर दास (1963) एसयूपीपी 2 एससीआर में दिए गए मामलों को प्राथमिकता देते हुए मुलेश्वर मणि व अन्य बनाम जगदीश प्रसाद व अन्य (2002) 2 एससीसी 468। रामकिशोरलाल बनाम कमल नारायण (1963) एसयूपीपी 2 एससीआर 417। राधा सुंदर दत्त बनाम मोहम्मद जहादूर रहीम व अन्य 1959 एससीआर 1309 तथा रामेश्वर बक्शसिंह व अन्य बनाम ठकुरायन बलराज कुंवर व अन्य एआईआर 1938 पीसी 187

5. श्रीमती कल्ला जग्गयम्मा द्वारा निष्पादित वसीयत के पैरा 6 का अंग्रेजी प्रतिपादन इस प्रकार हैं:

(6) दूसरा आइटम न्यू कॉलोनी में स्थित टाइल वाला घर जिसमें से पूर्वी विंग के 2 कमरे मेरी दूसरी बेटी चंदराम अप्पलानारसम्मा को दिए जाएंगे और पश्चिमी विंग के 2 कमरे मेरी बड़ी बेटी चंद्रम रामनम्मा को बिक्री, उपहार, बंधक आदि के पूर्ण अधिकार के साथ दिए जाएंगे। और यह मेरे निधन के बाद लागू होगा। मेरी बेटियों के निधन के बाद रखी गई और शेष संपत्ति केवल उनकी महिला बच्चों को हस्तांतरित होगी।

6. उपरोक्त को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता ने खंड (6) में उल्लिखित संपत्ति को अपनी बेटियों चंदाराम अप्पलानारसम्मा और चंदाराम रामनम्मा के पक्ष में बिक्री। उपहार। बंधक के पूर्ण अधिकारों के साथ वसीयत कर दी थी। आदि यह कि वसीयत पूर्ण रूप से थी। "बिक्री। उपहार। गिरवी आदि के पूर्ण अधिकार" शब्दों के उपयोग से स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गई थी। उपरोक्त खंड (6) में दिखाई दे रहा है। उस हद तक कोई कठिनाई नहीं है। बार में फोरेंसिक बहस का कारण वसीयत का उत्तरार्द्ध था। जिसके तहत वसीयकर्ता ने अपनी बेटियों की मृत्यु के बाद संबंधित संपत्ति के हस्तांतरण को विनियमित करने का प्रयास किया है। वसीयतकर्ता की इच्छा है कि उनकी बेटियों की मृत्यु के बाद उनमें निहित संपत्ति केवल उनकी महिला उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाएगी। सवाल यह है कि क्या वसीयतकर्ता श्रीमती कल्ला जग्गयम्मा ने दो वसीयतें की थी। एक जो संपत्ति को पूरी तरह से अपनी बेटियों के पक्ष में रखती थी और दूसरी जो उसी संपत्ति को अपनी महिला संतानों को सौंपती

थी। यदि हां। तो क्या दोनों वसीयतों का समाधान किया जा सकता है और यदि नहीं किया जा सकता है तो किसे प्रबल होना चाहिए।

7. इससे पहले कि हम इन प्रश्नों पर विचार करें, हम संक्षेप में ऊपर दिए गए निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं। विशेषकर इसलिए क्योंकि उच्च न्यायालय को उन निर्णयों द्वारा तय की गई कानूनी स्थिति में टकराव दिखाई देता है।

8. रामेश्वर बख्श सिंह के मामले में प्रिवी काउंसिल ने माना कि जहां एक पूर्ण संपत्ति वसीयत द्वारा वसीयतकर्ता के पक्ष में बनाई जाती है। वसीयत में अन्य खंड जो ऐसी पूर्ण संपत्ति के प्रतिकूल हैं, संपत्ति में कटौती नहीं कर सकते हैं लेकिन इसे अमान्य माना जाना चाहिए। निम्नलिखित परिच्छेद ने इस विषय पर कानून का सारांश दियाः

> "जहां एक पूर्ण संपत्ति वसीयत द्वारा वसीयतकर्ता के पक्ष में बनाई जाती है। तो वसीयत में जो खंड ऐसी पूर्ण संपत्ति के प्रतिकूल हैं। वे संपत्ति में कटौती नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अमान्य माना जाना चाहिए।"

9. राधा सुंदर दत्ता के मामले (lqizk) में यह न्यायालय एक ऐसी स्थिति से निपट रहा था जहां वसीयत में दिखाई देने वाले दो खंडों के बीच विरोधाभास था। इस न्यायालय ने पहले खंड के पक्ष में फैसला सुनाया, यह

मानते हुए कि बाद वाला खंड पहले खंड को रास्ता देगा। इस न्यायालय ने कहा:

> "-------जहां पहले वाले खंड और बाद वाले खंड के बीच विरोधाभास है और उन सभी को प्रभावी बनाना संभव नहीं है। वहां निर्माण का नियम अच्छी तरह से स्थापित है कि यह पहले वाला है वह खंड जो बाद के खंडों को ओवरराइड करना चाहिए न कि इसके विपरीत।"

10. रामकिशोर लाल के मामले (सुप्रा) में यह मुद्दा एक बार फिर इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। उस मामले में भी न्यायालय ऐसे मामले में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को लेकर चिंतित था, जहां वसीयतनामा के एक भाग में कही गई बातों और उसी दस्तावेज़ के दूसरे भाग में कही गई बातों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, खासकर जब पहले भाग में वसीयत पूर्ण है लेकिन दस्तावेज़ का बाद वाला भाग उसी संपत्ति के बारे में विपरीत दिशा देता है। इस न्यायालय ने माना कि इस तरह के संघर्ष की स्थिति में वसीयत में दिखाई देने वाले पहले खंडों द्वारा वसीयतकर्ता को प्रदत्त पूर्ण स्वामित्व को कम नहीं किया जा सकता है या छीना नहीं जा सकता है और यह स्वभाव के बाद के भाग में निहित निर्देशों पर लागू होगा। निर्णय का निम्नलिखित अंश शिक्षाप्रद है:

‘‘ऐसा कहा गया है कि निर्माण का स्वर्णिम नियम सभी शब्दों पर उनके सामान्य, प्राकृतिक अर्थों में विचार करने के बाद उपकरण के पक्षों के इरादे का पता लगाना है। इस इरादे को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय को संबंधित भाग पर विचार करना होगा समग्र रूप से दस्तावेज़ और उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा जिनके तहत विशेष शब्दों का उपयोग किया गया था। अक्सर शब्दों का उपयोग करने वाले पक्षों की स्थिति और प्रशिक्षण को ध्यान में रखना पड़ता है। यह ध्यान में रखना होगा कि बहुत से शब्दों का उपयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है और वह अर्थ अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग होता है। फिर यहां तक कि जहां एक विशेष शब्द का एक प्रशिक्षित संवाहक के लिए एक स्पष्ट और निश्चित महत्व होता है और वह उस अर्थ के बारे में निश्चित हो सकता है, जिसमें ऐसा संप्रेषक इसका उपयोग करेगा। जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है, जो संप्रेषण की कला में समान रूप से कुशल नहीं है तो शब्द की वही सख्त व्याख्या देना उचित और वाजिब नहीं हो सकता है। कभी-कभी संपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में दस्तावेजों के मामले में ऐसा होता है, चाहे वे वसीयतनामा हों या गैर

वसीयतनामा दस्तावेज़, कि दस्तावेज़ के एक भाग और दूसरे भाग में कही गई बातों के बीच स्पष्ट विरोधाभास है। इसका एक परिचित उदाहरण यह है कि दस्तावेज़ के पहले भाग में कुछ संपत्ति पूरी तरह से एक व्यक्ति को दी जाती है, लेकिन बाद में उसी संपत्ति के बारे में अन्य निर्देश दिए जाते हैं जो पहले भाग में दिए गए पूर्ण स्वामित्व से टकराते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। जहां ऐसा होता है वहां क्या किया जाना चाहिए ? यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस तरह के संघर्ष के मामले में पूर्ण स्वामित्व का पूर्व स्वभाव प्रबल होना चाहिए और स्वभाव के बाद के निर्देशों को पहले से दिए गए शीर्षक को प्रतिबंधित करने के असफल प्रयासों के रूप में नजरअंदाज किया जाना चाहिए। (देखें साहेबजादा मोहम्मद कामगार शाह बनाम जगदीश चंद्र देव धबल देव (1960) 3 एससीआर 604) हालांकि यह स्पष्ट है कि यदि संभव हो तो दस्तावेजों के दोनों हिस्सों को हमेशा सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह केवल तब संभव नहीं है, उदाहरण के लिए जहां एक पूर्ण शीर्षक स्पष्ट और सुथरा शब्दों में दिया गया है और बाद के प्रावधान उसी पर खरे उतरते हैं, तो बाद के प्रावधानों को शून्य माना जाना चाहिए।"

11. इसी आशय का मौलेश्वर मणि के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय है जहां एक बार फिर सवाल यह था कि क्या वसीयत के पहले भाग में वसीयतकर्ता द्वारा संपत्ति में बनाया गया पूर्ण हित छीन लिया जा सकता है या अप्रभावी बना दिया जा सकता है बाद की वसीयत द्वारा जो पहली वसीयत के प्रतिकूल है। प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने माना कि एक बार जब वसीयतकर्ता ने अपनी संपूर्ण संपत्ति में एक वसीयतकर्ता को पूर्ण अधिकार और हित दे दिया है, तो उसके लिए यह खुला नहीं है कि वह उसी संपत्ति को व्यक्तियों के दूसरे समूह के पक्ष में आगे दे सके।इस संबंध में निर्णय का निम्नलिखित अंश उपयुक्त है:

> ‘‘उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि एक बार जब वसीयतकर्ता ने अपनी संपूर्ण संपत्ति में एक वसीयतकर्ता को पूर्ण अधिकार और हित दे दिया है, तो वसीयतकर्ता के लिए यह खुला नहीं है कि वह उसी संपत्ति को उसी वसीयत में व्यक्तियों के दूसरे समूह के पक्ष में आगे दे सके, एक वसीयतकर्ता अपनी वसीयत में क्रमिक वसीयतकर्ता नहीं बना सकता है। पीछे का उद्देश्य यह है कि एक बार जब पहली वसीयतकर्ता में पूर्ण अधिकार निहित हो जाता है, तो वसीयतकर्ता पहली वसीयतकर्ता के उत्तराधिकार की रेखा को नहीं बदल सकता है। जहां एक वसीयतकर्ता ने किसी को

पूर्ण अधिकार प्रदान किया है, उसी संपत्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के पक्ष में की गई वसीयत बाद की वसीयत में पहली वसीयत के प्रतिकूल होगी और उसे अमान्य माना जाएगा।

इसलिए, हमारा विचार है कि एक बार जब वसीयतकर्ता ने पहले वसीयतकर्ता के पक्ष में एक पूर्ण संपत्ति दे दी है, तो उसके लिए यह खुला नहीं है कि वह उसी संपत्ति को दूसरे व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत कर सके।''

12. प्यारे लाल के मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने माना कि वसीयत की व्याख्या करते समय न्यायालय को स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी शर्तों में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से दस्तावेज़ को समग्र रूप से लेना चाहिए। इस न्यायालय ने वसीयत की व्याख्या के मामले में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को मान्यता दी:

''(क) यदि संभव हो तो संपूर्ण वसीयत को पढ़ने वसीयतकर्ता का इरादा के द्वारा ऐसे निर्माण को स्वीकार किया जाना चाहिए जो प्रत्येक अभिव्यक्ति को कुछ प्रभाव देगा, न कि जो किसी भी अभिव्यक्ति को निष्क्रिय कर सकता हैः (ख) एक और नियम यह है कि वसीयत में एक से अधिक बार आने वाले शब्दों को हमेशा एक ही अर्थ में

उपयोग किया जाना माना जाएगा जब तक कि वसीयत से कोई विपरीत इरादा प्रकट न होः (ग) वसीयत के सभी हिस्सों को एक-दूसरे के संबंध में समझा जाना चाहिए, (घ) अदालत उन परिस्थितियों को देखेगी जिनके तहत वसीयतकर्ता अपनी वसीयत करता है, जैसे कि उसकी संपत्ति की स्थिति, उसके परिवार की स्थिति और इसी तरह, (ड) जहां स्पष्ट रूप से विरोधाभासी स्वभाव को इस्तेमाल किए गए प्रत्येक शब्द को पूर्ण प्रभाव देकर समेटा जा सकता है एक दस्तावेज़, एक निर्माण के बजाय ऐसे निर्माण को स्वीकार किया जाना चाहिए जिसका प्रभाव वसीयतकर्ता द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ को कम करने पर होगा, (च) जहां दो उचित निर्माण में से एक से निर्वसीयत की स्थिति पैदा होगी, वह होना चाहिए। ऐसे निर्माण के पक्ष में खारिज कर दिया गया जो ऐसा कोई व्यवधान पैदा नहीं करता।''

13. रामचंद्र शेनॉय के मामले (सुप्रा) में यह अदालत एक ऐसे मामले से निपट रही थी जहां वसीयतकर्त ने अपनी बेटी के पक्ष में एक वसीयत बनाई थी और अपनी (बेटी के) पुरुष बच्चों के पक्ष में एक उपहार दिया था। वसीयत के प्रासंगिक भाग का निम्नलिखित प्रभाव से अंग्रेजी में अनुवाद किया गयाः

> ‘‘ये सभी (संपत्तियां) मेरे बाद मेरी बड़ी बेटी सेवेरिना सबीना को और उसके जीवनकाल के बाद उसके पुत्रों को भी स्थायी और पूर्ण हकदारों के रूप में प्राप्त होंगी।’’

सवाल यह था कि क्या वसीयतकर्ता ने बेटी के लिए पूर्ण वसीयत की थी या केवल जीवन हित बनाया था, जिसके बाद वसीयतकर्ता के पोते-पोतियों के पक्ष में पूर्ण वसीयत की गई थी। इस न्यायालय ने वसीयत की व्याख्या पर कहा कि जो बेटी के पक्ष में बनाया गया था वह केवल एक जीवन संपत्ति थी और वसीयतकर्ता का इरादा अपनी बेटी के माध्यम से अपने पोते के पक्ष में पूर्ण वसीयत करना था। इस संबंध में निर्णय का निम्नलिखित अंश उपयुक्त हैः

> ‘‘यह सामान्य आधार था कि खंड 3 (सी) के तहत वसीयतकर्ता का इरादा अपनी बेटी के पुरुष बच्चों पर पूर्ण और स्थायी हित प्रदान करने का था, हालांकि अगर अपीलकर्ताओं द्वारा आग्रह किए गए तर्कों को स्वीकार कर लिया गया तो उनके पक्ष में विरासत शून्य हो जाएगी क्योंकि वहां कानूनी तौर पर अपनी मां के पक्ष में पूर्ण हित के बाद कोई उपहार नहीं दिया जा सकता है। यह इस सिद्धांत पर है कि जहां संपत्ति पूरी तरह से ए को दी जाती है, तो ए की मृत्यु के बाद जो कुछ भी बचता है वह उसके

उत्तराधिकारियों को या उसकी वसीयत के तहत पारित होना चाहिए और किसी भी तरह से अलग करने का प्रयास किया जाना चाहिए एक अलग गंतव्य निर्धारित करके पूर्ण हित की घटनाओं को बनाए गए हित के प्रतिकूल होने के कारण विफल होना चाहिए। लेकिन विचार के लिए प्रारंभिक प्रश्न यह है कि क्या वसीयत के उचित निर्माण पर सेवेरिना के पक्ष में पूर्ण हित स्थापित होता है। यह इनमें से एक वसीयत के निर्माण के मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस हद तक यह कानूनी रूप से संभव है, उस सीमा तक वसीयत में निहित प्रत्येक स्वभाव पर प्रभाव दिया जाना चाहिए, जब तक कि कानून इसे प्रभाव देने से नहीं रोकता है। निःसंदेह, यदि क्रमिक हितों को प्रदान करने वाले दो प्रतिकूल प्रावधान हैं, यदि बनाया गया पहला हित वैध है तो बाद वाला हित प्रभावी नहीं हो सकता है, लेकिन निर्माण न्यायालय प्रतिकूलता से बचने के लिए यथासंभव दूर तक आगे बढ़ेंगे, ताकि वसीयत में निहित प्रत्येक वसीयती इरादे को यथासंभव प्रभावी बनाया जा सके। यह इस कारण से है कि जहां ए को कोई वसीयत दी गई है, भले ही वह स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से हो और उसके बाद बी को ए की मृत्यु पर ''पर'' या ''बाद'' में या ''पर'' एक उपहार दिया गया हो, वहां

ए को प्रथम दृष्टया जीवन हित दिया माना जाता है और बी को शेष में हित लेने के लिए, बी के पक्ष में बनाए गए हित को समायोजित करने के लिए ए के स्पष्ट रूप से पूर्ण हित में कटौती की जा रही है। वर्तमान मामले में, जैसा कि स्वीकार किया जाना चाहिए, वसीयतकर्ता ने एक प्रदान करने का इरादा किया था सेवेरिना के पुरुष बच्चों में पूर्ण रुचि, सवाल यह है कि क्या इस पर प्रभाव डाला जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। यदि सेवेरिना के हित को पूर्ण माना जाता तो निस्संदेह प्रभाव उक्त इरादे पर नहीं डाला जा सकता था। लेकिन अगर वसीयत में ऐसे शब्द हैं जो एक उचित निर्माण पर यह दर्शाते हैं कि सेवेरिना का हित पूर्ण नहीं था, बल्कि केवल उसके जीवन तक ही सीमित था, तो न्यायालय के लिए इस तरह के निर्माण को अपनाना उचित होगा, क्योंकि ऐसा होगा वसीयत में निहित प्रत्येक वसीयतनामा स्वभाव को प्रभावी बनाएं। यह उस संदर्भ में है कि खंड (सी) में आने वाले शब्द उसके जीवनकाल के बादश् महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। ये शब्द यह दर्शाते हैं कि निम्नलिखित शब्दों द्वारा नामित व्यक्तियों को उसके बाद, यानी उत्तराधिकार में, न कि उसके साथ संयुक्त रूप से रुचि लेनी थी और इसलिए जब तक कि पुरुष बच्चों

को दिए गए ब्याज का जिक्र करने वाले शब्दों को केवल सीमा के शब्द नहीं माना जाता, यानी, सेवेरिना द्वारा स्वयं लिए जाने वाले ब्याज की गुणवत्ता को दर्शाने के लिएए न कि खरीद के शब्दों के रूप में, इसका एकमात्र उचित निर्माण संभव है खंड यह मानेगा कि सेवेरिना के पक्ष में बनाया गया हित केवल एक जीवन हित था और शेष राशि उसके पुरुष बच्चों को प्रदान की गई थी।''

14. कैवेलिक्कल अंबुन्ही के मामले (सुप्रा) में न्यायालय ने अधिकतम ''कम डुओ इंटर से पुगनंटिया रिपेरिअनटुर इन टेस्टामेंटो अल्टीमेट रैटम एस्ट लागू किया, जिसका अर्थ है कि यदि किसी वसीयत में दो प्रावधान हैं तो बाद वाला पहले वाले पर प्रबल होगा।

15. अब समय आ गया है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों को देखें, जिसका अध्याय 6 वसीयत के निर्माण से संबंधित है। वसीयत की व्याख्या के कुछ सिद्धांत जिन्हें अध्याय 6 में वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, धारा 84 में यह प्रावधान है कि यदि कोई खंड दो अर्थों के लिए अतिसंवेदनशील है, जिनमें से एक के अनुसार इसका कुछ प्रभाव है और दूसरे के अनुसार इसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, तो पहले वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह धारा 85 में

यह प्रावधान है कि वसीयत के किसी भी हिस्से को अर्थहीन मानकर खारिज नहीं किया जाएगा, यदि उस पर उचित निर्माण करना संभव हो। धारा 86 में प्रावधान है कि यदि एक ही शब्द एक ही वसीयत के विभिन्न भागों में आता है, तो उन्हें हर जगह एक ही अर्थ में उपयोग किया गया माना जाएगा जब तक कि कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो। धारा 87 यह स्पष्ट करती है कि वसीयतकर्ता के इरादे को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाएगा क्योंकि यह पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता है, और यह प्रभाव उसे यथासंभव दिया जाना चाहिए। धारा 88 में प्रावधान है कि यदि वसीयत में उपहार के दो खंड हैं, जो असंगत हैं, ताकि वे संभवतः एक साथ खड़े न हो सकें, तो अंतिम मान्य होगा।

16. ऊपर उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि वसीयत की व्याख्या करते समय, न्यायालय जहां तक संभव हो ऐसी व्याख्या करेंगे जिससे वसीयत के किसी भी हिस्से को अनावश्यक होने से बचाया जा सके। इसलिए जहां तक संभव हो, अदालतें वसीयतकर्ता के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए वसीयत की व्याख्या करेंगी। ऐसा कहने के बाद, हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि वसीयत की व्याख्या से संबंधित न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय शायद ही कभी सहायक होते हैं, सिवाय उस हद तक जब वे सामान्य अनुप्रयोग के कानून के प्रस्ताव को मान्यता देते हैं या निर्धारित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक दस्तावेज़ की व्याख्या उन विशिष्ट परिस्थितियों में की जानी चाहिए जिनमें

उसे निष्पादित किया गया है और वसीयतकर्ता द्वारा प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए। यह वास्तव में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 82 की आवश्यकता है क्योंकि इसमें प्रावधान है कि वसीयत में किसी भी खंड का अर्थ पूरे दस्तावेज़ से एकत्र किया जाना चाहिए और सभी हिस्सों को एक दूसरे के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

17. मामले के मौजूदा तथ्यों की बात करें तो ऊपर दी गई वसीयत के खंड 6 को ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह वसीयकर्ता की बेटियों के पक्ष में एक स्पष्ट और पूर्ण वसीयत करता है। ''बिक्री, उपहार, गिरवी आदि के पूर्ण अधिकार'' जैसे शब्दों का प्रयोग वसीयतकर्ता द्वारा नियोजित वसीयतकर्ता के इरादे को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। यहां वादी प्रतिवादियों के विद्वान वकील को भी इस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं था कि वसीयकर्ता ने बिना किसी अनिश्चित शर्तों के अपनी बेटियों के पक्ष में पूर्ण वसीयत कर दी थी। उनके द्वारा तर्क दिया गया था कि इस प्रकार की गई वसीयत को जीवन संपत्ति के रूप में माना जा सकता है, इसलिए नहीं कि वसीयत में ऐसा कहा गया है, बल्कि इसलिए कि जब तक इसे खंड 6 का दूसरा भाग नहीं माना जाता है, जिसके द्वारा वसीयत करने वालों की महिला संतानों को संपत्ति नहीं मिलेगी। इसी आधार पर यह तर्क दिया गया कि श्रीमती सदाराम अप्पलानारसम्मा की पूर्ण संपत्ति को केवल एक जीवन संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए। हालाँकि यह विवाद पहली नज़र में आकर्षक है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर यह टिक नहीं पाता

है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी दस्तावेज़ की व्याख्या का अंतिम उद्देश्य वर्तमान मामले वसीयकर्ता में निष्पादक के वास्तविक इरादे की खोज करना और उसे क्रियान्वित करना है। हम यहां उस मामले से निपट नहीं रहे हैं जहां वसीयतकर्ता ने वसीयत के एक हिस्से में संपत्ति ''ए'' को दे दी है, जबकि वही संपत्ति दूसरे हिस्से में ''बी' को दे दी गई है। यदि ऐसा कोई संघर्ष होता, तो वादी- प्रतिवादी के लिए यह तर्क देना संभव होता कि बाद वाली वसीयत को पहले की तुलना में प्राथमिकता में प्रभावी होना चाहिए। इसके विपरीत हम एक ऐसे मामले से निपट रहे हैं जहां वसीयतकर्ता का अपनी बेटियों के पक्ष में पूर्ण वसीयत करने का इरादा स्पष्ट है। दूसरे, अभिव्यक्ति ''मेरी बेटियों के निधन के बाद रखी गई और शेष संपत्ति केवल उनकी महिला बच्चों को हस्तांतरित की जाएगी' वसीयतकर्ता की बेटियों के पक्ष में पहले की गई वसीयत के विपरीत एक वसीयत नहीं है। ऊपर दी गई अभिव्यक्ति बेटियों के पक्ष में वसीयत की पूर्ण प्रकृति को ख़राब नहीं करती है। खंड 6 के उत्तरार्द्ध भाग द्वारा वसीयतकर्ता का उद्देश्य उनकी महिला संतानों को वह सारी संपत्ति हस्तांतरित करना था जो उनके निधन के समय वसीयतकर्ताओं के हाथों में उपलब्ध थी। यदि वसीयतकर्ता उन्हें वसीयत की गई संपत्ति को बेचने या उपहार में देने का निर्णय लेते हैं, तो स्पष्ट रूप से उक्त खंड के संदर्भ में महिला संतानों को ऐसी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होगा, क्योंकि वसीयत की शर्तों के तहत वास्तव में उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार

था। इस प्रकार देखा, पूर्ण वसीयत के बीच कोई वास्तविक संघर्ष नहीं है, जो वसीयत के खंड 6 का पहला भाग करता है और उक्त खंड का दूसरा भाग, जो वसीयतकर्ताओं के हाथों में कुछ बचा है उसके हस्तांतरण के संबंधित है। खंड 6 के दो भाग अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, अर्थात् एक बेचने, उपहार देने, गिरवी रखने आदि के अधिकारों के साथ वसीयतकर्ताओं पर पूर्ण स्वामित्व निहित करता है और दूसरा उनके द्वारा ऐसी बिक्री, उपहार या हस्तांतरण से बच सकने वाली चीज़ों के हस्तांतरण को विनियमित करता है। उत्तरार्द्ध भाग इस तथ्य के कारण अनावश्यक है कि वह अपनी बेटियों के पक्ष में पूर्ण वसीयत करने के वसीयतकर्ता के स्पष्ट इरादे के प्रतिकूल था। यह निरर्थक भी हो सकता है क्योंकि उत्तराधिकारियों ने पूर्ण स्वामित्व और बिक्री के अपने अधिकारों का प्रयोग किया जिससे ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो अगली पीढ़ी की महिलाओं या किसी अन्य के हिस्से में आ सके। सभी ने कहा कि खंड 6 के दूसरे भाग में की गई शर्त से वसीयतकर्ताओं को वसीयत की गई संपत्ति के पूर्ण मालिक होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिणाम यह होगा कि उनके निधन पर उनके स्वामित्व वाली संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार के सामान्य कानून के अनुसार हस्तांतरित होगी, न कि वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार।

18. परिणामस्वरूप यह अपील सफल होती है और इसके द्वारा अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को

रद्द कर दिया गया है और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को बहाल कर दिया गया है। कोई लागत नहीं।

अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पियूष कुमार मेडतिया, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।